Hkkjr ds Ñf"k fodkl esa ckxokuh % ,d v/;;u

सुनील कुमार चौधरी (ICSSR DOCTORAL FELLOW),
डॉ. (श्रीमति) शारदा शिंदे,

सारांश

यह शोध पत्र ''भारत के कृषि विकास में बागवानीः एक अध्ययन'' पर केन्द्रित है, क्योंकि कृषि देश के आर्थिक विकास की कुंजी है, जो आर्थिक विकास के प्रमुख घटकों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है, लेकिन पिछले दशकों से कृषि के समक्ष अनेक चुनौतियॉ उभरी हुई है, जिसके कारण पिछले दशक कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, जिससे देश में खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई और इसी बीच कृषकों की दयनीय स्थिति के कारण देश में कृषकों के आत्महत्या करने के प्रतिशत में वृद्धि हुई है, जिससे देश की राजनीति एवं आर्थिक गतिविधियों में उथल–पुथल मची। इसके अलावा देश के सम्मुख आज खाद्य सुरक्षा एवं पोषाहारीय सुरक्षा, रोजगार सृजन, आय में असमानता, गरीबी उपशमन जैसी समस्याऍ सरकार का गला घोट रही है। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नीतिगत पहलों एवं समग्र कृषि विकास की अभिसरंचना को सरकार ने विकास की नीतियों में प्रमुखता से शामिल किया है और सरकार ने कृषि विकास पर प्रमुखता से ध्यान देना शुरू किया है, जिसमें कृषि के समग्र क्षेत्रों के विकास की पहल की गई है जिसमें से बागवानी क्षेत्र उभरा है।

बागवानी कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी शाखा है और बागवानी का कृषि में व्यापक स्थान है, क्योंकि बागवानी में बहुत सी फसलें शामिल है, जिनमें फल, सब्जियॉ, कंद–मूल फसलें, फल, सजावटी, सुगंधित और औषधीय पौधे, मसालें, पौधीय फसलें, मशरूम, बांस, कोको, आलू आदि है जो कृषि क्षेत्र में विविधीकरण को सरल बनाती है। आज बागवानी फसलें उगाना आजीविका की सुरक्षा सुधारने, रोजगार सृजन बढ़ाने और पोषाहारीय सुरक्षा प्राप्त करने, मूल्यवर्धन के जरिए आय बढ़ाने का एक विकल्प है। देश में बागवानी विकास की काफी संभावनाऍ मौजूद है और इसके विकास की प्रमुख योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन एक ज्योति के रूप में कार्य कर रही हैं। अतः बागवानी विकास कृषि विकास का नवप्रवर्तन है ।

शब्दकुंजी: एन.एच.एम., बागवानी, विविधीकरण, पोषाहारीय सुरक्षा, उत्पादन प्रवृत्ति, रोजगार सृजन।

रिसर्च स्कॉलर,
अर्थशास्त्र अध्ययनशाला,
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

प्राध्यापक – अर्थशास्त्र
शा. माधव कला,वाणिज्य एवं विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

Email - Choudhary_sunil@live.com, h.gupta@live.com

प्रस्तावनाः

कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तथा विकास की कुंजी है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के विकास के प्रमुख घटकों में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। इस तरह से देश के आर्थिक विकास में कृषि की अहम् भूमिका देखी गई है। अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि का महत्त्व अधिक बढ़ जाता है जब देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 56 प्रतिशत भाग वर्षा पर निर्भर करता है और अनिश्चिता के कारण अपेक्षाकृत विनिवेश की मात्रा भी कम है, लेकिन इसके बावजूद भी कृषि का महत्त्व उल्लेखनीय है। कृषि का देश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 1950–51 में 54.40 प्रतिशत योगदान था जो घटकर वर्ष 2010–11 में 14.2 प्रतिशत (2004–05 की कीमत पर) रह गया, जबकि देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 58 प्रतिशत भाग कृषि एवं संबंध क्रियाओं से अपनी आजीविका को सुरक्षित करता है। भारत के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग कृषि से ही जुड़ा हुआ है। वर्ष 2009–10 में देश के निर्यात में कृषि और संबंध वस्तुओं का अनुपात 9.9 प्रतिशत था, अप्रैल–सितम्बर 2010–11 के दौरान यह घटकर 8.5 प्रतिशत रह गया है[1]। डब्लू.टी.ओ. द्वारा प्रकाशित विश्व व्यापार रिपोर्ट 2010 के अनुसार वर्ष 2009 में कृषि में विश्व व्यापार के 1.4 प्रतिशत के अंश के साथ भारत का कृषि निर्यात वर्ष 2008–09 में 85951.56 करोड़ रू. से बढ़कर वर्ष 2009–10 में लगभग 4.16 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 89522.89 करोड़ रू. हो गया है। देश के कुल निर्यात में 2008–09 के दौरान कृषि निर्यात का अंश 10.22 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2009–10 में 10.59 प्रतिशत हो गया है और कृषि उत्पाद का एक बहुत बड़ा भाग देश की खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में खर्च हो जाता है, इसके अलावा कृषि औद्योगिक विकास के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करता है। कृषि के महत्त्व को देखते हुए सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकता देते हुए इसके विकास की पहल शुरू की है, जिसके चलते वर्ष 1966–67 में देश में हरित क्रांति आई और इसके परिणामस्वरूप देश खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुका है लेकिन बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण मनुष्य के स्वार्थी भाव ने कृषि के सम्मुख अनेक चुनौतियॉ को ला खड़ा किया है जिससे देश की कृषि, उत्पादकता में कमी एवं पिछडेपन की कगार पर है जिसके कारण आज भी भारत देश, खाद्य एवं पौष्टिक आहार की सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा पा रहा है और पिछले दो दशकों से कृषि की दयनीय स्थिति के कारण कृषकों की आय में कमी एवं कर्ज के बोझ से कृषकों की आत्महत्या की प्रवृति में बढ़ोत्तरी हुई है, साथ ही 40 प्रतिशत कृषक परिवार कृषि कार्यो को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में हस्तान्तरित हुए है[2]। लेकिन इन सबके बावजूद भी विश्व स्तर पर कृषि उत्पाद वस्तुओं में भारत का दूसरा स्थान है, हालांकि देश के समक्ष अनेक चुनौतियॉ विद्यमान है जिनमें से खाद्य सुरक्षा, रोजगार, पौष्टिक आहार की उपलब्धता, कुपोषण, गरीबी, आय की असमानता, एवं सतत विकास आदि विकराल समस्याऍ है लेकिन वर्तमान परिदृश्य में फसल प्रतिरूप व मांग में परिवर्तन के कारण कृषि क्षेत्र में विविधीकरण का विस्तार हुआ है जिससे कृषि क्षेत्र के विकास को गति मिली है और इसका श्रेस्य बागवानी है ।

कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी शाखा बागवानी है जिसका कृषि क्षेत्र में व्यापक स्थान है। क्योंकि बागवानी के अंतर्गत बहुत सी फसले शामिल होती है जो कृषि क्षेत्र को विस्तृत कर विकास को उन्मुख करती है और यह देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की स्थिति को मजबूत करती है। बागवानी का कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान है क्योंकि भारत की कुल कृषि सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में बागवानी का 30 प्रतिशत हिस्सा जो केवल 13.08 प्रतिशत के फसल क्षेत्र से प्राप्त है जबकि कुल कृषि निर्यात वस्तुओं में 37 प्रतिशत बागवानी से उपलब्ध है[2]। और देश की कुल श्रम शक्ति का 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को

आजीविका प्रदान करती है। भारत बागवानी उत्पादन में विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है जबकि कुछ बागवानी फसलों के उत्पादन में शीर्ष पर है अतः बागवानी का महत्त्व आज दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है।

कृषि उत्पादकता में वृद्धि, रोजगार सृजन, पौष्टिक आहार की सुरक्षा, आय में समानता, गरीबी का उपशमन, जैविक कृषि, और कृषि क्षेत्र में विविधीकरण, कृषि भूमि का विस्तार के संदर्भ में बागवानी का महत्त्व अधिक विस्तृत है भारत में बागवानी विकास की दशाएँ विश्व की तुलना में अधिक अनुकूल है जिससे देश में बागवानी विकास की संभावनाएँ अधिक मौजूद है। देश में बागवानी विकास की पहल सातवीं पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के साथ की गई थी लेकिन यह नवीं एवं दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रमुखता के साथ देखी गई है और इस बीच बागवानी विकास अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सकारात्मक रूप में दृष्टिगोचर हुआ है। अतः इस तरह से बागवानी विकास देश की कृषि के समग्र एवं सतत विकास को उन्मुख कर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है।

<u>अध्ययन के उद्धेश्यः</u> यह शोध पत्र अध्ययन के निम्न बिन्दुओं पर केन्द्रित है—

1. कृषि विकास में बागवानी के योगदान का अध्ययन करना।
2. बागवानी विकास की पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
3. मुख्य कृषि फसलों की उत्पादन प्रवृति का अध्ययन करना।
4. देश में बागवानी के विकास एवं विस्तार का अध्यन करना।
5. राष्ट्रीय बागवानी मिशन का संक्षिप्त अध्ययन करना।
6. देश में बागवानी विकास की संभावनाओं का अध्ययन करना।

<u>शोधप्रविधिः</u> यह शोधपत्र द्वितीय संमकों पर आधारित है जिसमें हमारे द्वारा विभिन्न उपयुक्त सम्बन्धित दस्तावेजों एवं प्रलेखों और प्रपत्रों से संमकों को एकत्रित कर उनका सारणीयन, वर्गीकरण, सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करके निष्कर्षन किया गया है। जिसमें से प्रमुख बेबसाइट एनएचएम, एनएचबी एवं कृषि विकास एवं विभिन्न वार्षिक परिपत्रों का अध्ययन कर, उद्धेश्यों की प्राप्ति की गई हैं।

<u>बागवानी से आशयः</u> बागवानी फल, सब्जियॉ, कंद—मूल, पौधीय फसलें, मसालें, फूल, सजावटी, सुगंधित और औषधीय फसले के उगाने और उनके प्रसंस्करण, प्रबंधन, और विपणन का विज्ञान है लेकिन बागवानी की नई परिभाषा में विस्तार हुआ है जिसमें फल, सब्जियॉ, मसालें, कंद मूल फसलें, औषधीय एवं पौधीय फसलों के अतिरिक्त वर्तमान में मशरूम, बांस, एवं मधुमक्खी पालन के व्यवसाय को भी शामिल किया गया है, जिससे कृषि विकास के विकल्पों के अवसरों का सृजन हुआ है और यह कृषि क्षेत्र में विविधकरण को विस्तृत करता है।

<u>बागवानी विकास की पृष्ठभूमिः</u> देश में कृषि विकास मानवीय सभ्यता के विकास के फलस्वरूप उद्गम हुआ है लेकिन इस समय कृषि का उपयोग सिर्फ खाद्यान्न की आपूर्ति एवं जीविकोपार्जन तक सीमित थी किन्तु जैसे—जैसे मानवीय विकास हुआ, वैसे वैसे ही कृषि के स्वरूप में विस्तार हुआ है और आज कृषि

सिर्फ जीविकोपार्जन का साधन मात्र न होकर एक व्यवसाय के रूप में उभरा है इस कारण से कृषि विकास के अवयवों में परिर्वतन हुआ है। इन परिवर्तनों में बागवानी क्षेत्र प्रमुखता से उभरा है जो कृषि विकास को परिलक्षित करता है क्योंकि देश में औद्योगिकरण, शहरीकरण एवं वैश्वीकरण से बागवानी फसलों की मांग बढ़ी है और देश में बागवानी विकास की सर्वाधिक अनुकूलतम दशाएँ मौजूद है, जिससे देश में बागवानी विकास तीव्र रूप से उदृत हुआ है। देश में बागवानी विकास की पहल अस्सी के दशक में स्पष्ट रूप में देखी गई है जिसके द्वारा वर्ष 1984 में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड़ की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्धेश्य बागवानी विकास करना था लेकिन बढ़ती मांग के कारण बागवानी विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन वर्ष 2005–06 में प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 2011–12 तक देश में बागवानी उत्पादन 300 मिलियन टन करने तथा बागवानी के तहत् बुआई क्षेत्र को 40 लाख हेक्ट. करने का लक्ष्य इस मिशन के तहत् निर्धारित किया गया है। पोषक उपजों की उपलब्धि में वृद्धि, कृषकों की आय में वृद्धि आदि उद्धेश्यों में शामिल है। देश में बागवानी विकास कृषि विकास में उभरते हुये पायदान के रूप में निखरा है, जिसके कारण विश्व में कृषि उपज वस्तुओं में भारत का दूसरा स्थान हैं क्योंकि देश में बागवानी उत्पादन वर्ष 1991–92 में 28.63 मिलियन टन था, जो बढ़कर 2007–08 में 207.01 मिलियन टन हो गया। बागवानी उत्पादन में इस वृद्धि के चलते देश में फलों व सब्जियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धि में भी वृद्धि हुई है और इन उपजों से निर्यात प्राप्तियॉ 1991–92 में 141.1 करोड़ रूपए की थीं, जो बढ़कर 2002–03 में 6759.3 करोड़ रू. की रही। देश में बागवानी फसलों के लिए अधीन क्षेत्रफल वर्ष 2007–08 के दौरान 200. 87लाख हेक्ट. था[1]। इस प्रकार से बागवानी एक फलता व्यवसाय है जो कृषि क्षेत्र में विविधकरण व कृषि विकास के अवसरों को सृजित करके, कृषि विकास को पोषित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

<u>भारत में कृषि फसलों की उत्पादन प्रवृत्तिः</u> देश में कृषि फसलों की उत्पादन, क्षेत्रफल एवं उत्पादकता की प्रवृत्ति को निम्न तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है[3]–

<u>तालिका क्र.1</u>

<u>भारत में मुख्य कृषि फसलो का उत्पादन एवं उत्पादकता</u>

फसल	क्षेत्र (लाख हैक्ट.)			उत्पादन (मिलियन टन)			उपज (किग्रा./हैक्ट.)		
	2007-08	**08-09**	**09-10**	**07-08**	**08-09**	**09-10**	**07-08**	**08-09**	**09-10**
खाद्यान्न	1240.68	1228.32	1213.66	230.78	234.47	218.20	1860	1909	1798
तिलहन	266.93	275.58	261.08	29.76	27.72	24.93	1115	1006	955
गन्ना	50.55	44.15	42.02	348.19	285.03	273.75	68877	64553	66099
कपास@	94.14	94.07	103.10	25.88	22.28	23.44	467	403	395

नोटः (@ उत्पादन प्रत्येक 170 किग्रा. की मिलियन गांठें)

स्रोतः– वार्षिक रिपोर्ट (2010–11) कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि देश में वर्ष 2007–08 में खाद्यान्न उत्पादन 230.78 मिलियन टन था किन्तु मानसून अनिश्चिता के कारण वर्ष 2009–10 में इसके उत्पादन में गिरावट होकर 218.20 मिलियन टन रहा है इसी तरह से तिलहन, गन्ना एवं कपास के क्षेत्र में उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई है। लेकिन इसके पश्चात कृषि उपजों में वृद्धि का प्रतिशत रहा है।

भारत में खाद्यान्न उपज की प्रवृत्ति (सीजन वाईज): देश में कृषि क्षेत्र में विगत वर्षो से काफी उतार–चढ़ाव बना हुआ है। मानसून, पर्यावरण, भूअधिग्रहण एवं कृषकों की आय का निम्न स्तर आदि उत्पादन एवं उनके क्षेत्र में वृद्धि एवं कमी के जिम्मेदार घटक है। देश में खाद्यान्न उत्पादन की प्रवृति को तालिका क्रमांक 2 से स्पष्ट समझा जा सकता है[4]–

तालिका क्र.2

भारत में खाद्यान्न अनाज का क्षेत्र, उत्पादन, एवं उपज (सीज़न वाईज़)

(क्षेत्रः मिलियन हैक्ट., उत्पादनः मिलियन टन, उपजः किग्र./हैक्ट.)

वर्ष	खरीफ			रबी			कुल खाद्यान्न अनाज		
	क्षे.	उत्पा.	उपज	क्षे.	उत्पा.	उपज	क्षे.	उत्पा.	उपज
2005-06	*72.72*	*109.87*	*1511*	*48.88*	*98.73*	2020	121.69	208.60	1715
2006-07	*72.67*	*110.58*	*1522*	*51.04*	*106.71*	2091	123.71	217.28	1758
2007-08	*73.56*	*120.96*	*1644*	*50.51*	*109.82*	2174	124.07	230.78	1860
2008-09	*71.43*	*118.14*	*1654*	*51.40*	*116.33*	2263	122.83	234.47	1909
2009-10	*69.33*	*103.84*	*1498*	*52.04*	*114.36*	2197	121.37	218.20	1798
2010-11	69.05	114.63	1660	-	-	-	-	-	-

स्रोतः सांख्यकीय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में कृषि क्षेत्र में खाद्यान्न अनाजो के उत्पादन एवं उनके उत्पादन और उनकी उत्पादकता में उतार–चढ़ाव की स्थिति बनी है, जिसमें वर्ष 2005–06 में खरीफ का क्षेत्रफल 72.72 मिलियन हैक्ट. से 109.87 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है, इसकी उपज प्रति हैक्ट. 1511 किग्रा रही और वर्ष 2009–10 में खरीफ का बोया गया क्षेत्र 69.33 मिलियन हैक्ट. में 103.84 मिलियन टन का खाद्यान्न अनाज का उत्पादन हुआ और इसकी उत्पादकता 1498 किग्र/हैक्ट रही और वर्ष 2010–11 में खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन 114.63 मिलियन टन, 69.05 मिलियन हैक्ट. क्षेत्र से हुआ है। इसी प्रकार से रबी के खाद्यान्न उपजों में देखा गया है और वर्ष 2009–10 में देश में कुल खाद्यान्न उपजों का 121.37 मिलियन हैक्ट. क्षेत्र से 218.20 मिलियन टन का उत्पादन प्राप्त किया है।

भारत में बागवानी फसलों की उत्पादन प्रवृतिः भारत में बागवानी फसलों की उत्पादन प्रवृत्ति में लगातार वृद्धि दर्ज की गई लेकिन वृद्धि मिशन के क्रियान्वयन के पश्चात् अधिक तीव्रतम रूप में देखी गई है जिसमें से देश में फलों और सब्जियों के क्षेत्र में अधिक वृद्धि रही है जिससे प्रति व्यक्ति की उपलब्धता में भी वृद्धि हुई हैं । भारत में बागवानी फसलों के उत्पादन प्रवृति को निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया है[5]—

तालिका क्र.3

भारत में मुख्य बागवानी फसलो का क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता

(क्षेत्र 000′ हैक्ट., उत्पादनः 000′ मीट्रिक टन, उपजः मीट्रिक / हेक्ट..)

वर्ष	फल			सब्जियॉ			मसालें			पौधीय फसले		
	क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्र	उत्पादन	उत्दा.	क्षेत्र	उत्पादन	उत्पा.	क्षेत्र	उत्पादन	उत्पा.
1991-92	2874	28632	10.0	5593	58532	10.5	2005	1900	0.1	2298	7498	3.3
2000-01	3869	43138	11.1	6250	93850	15.0	2500	3765	1.2	2862	9458	3.3
2004-05	5049	50867	10.1	6744	101246	15.0	3150	4001	1.3	3147	9835	3.1
2005-06	5324	55356	10.04	7213	114993	15.4	2366	3705	1.6	3283	11263	3.4
2007-08	5857	65587	11.2	7848	128449	16.4	2617	4357	1.7	3190	11300	3.5
2008-09	6101	68466	11.2	7981	129077	16.2	2629	4145	1.6	3217	11336	3.5
2009-10	6329	71516	11.3	7985	133738	16.7	2464	4016	1.6	3265	11928	3.7

स्रोतः बागवानी डाटाबेस, 2010 (एन.एच.बी.)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि देश में बागवानी विकास में लगातार वृद्धि हुई है और बागवानी फसलों की उत्पादकता भी अधिक रही है। वर्ष 2009—10 में फलों का उत्पादन 71516 हजार मीट्रिक टन, 6329 हजार हैक्ट. क्षेत्र से हुआ है इसी तरह से सब्जियों और मसालें एवं पौधीय फसलों के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई हैं।

बागवानी विकास कार्यक्रमः देश में बागवानी विकास, कृषि एवं सहकारिता विभाग के विकासात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा रहा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन, लघु सिंचाई, राष्ट्रीय बांस मिशन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजना एन. एच.एम. और नारियल विकास बोर्ड द्वारा नारियल समन्वय पर प्रौद्योगिकी मिशन सहित समेकित नारियल विकास और इसके अलावा मानव संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर की 13 ऐजेंसियों के माध्यम से कार्यों का संचालन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.): राष्ट्रीय बागवानी मिशन केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित एकीकृत कार्यक्रम है जो कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा दसवीं पंचवर्षीय के दौरान 5 मई 2005 से सभी देश के 18 राज्यों और 3 शासित प्रदेश और 371 जिलों में शुरूआत की गई है। यह मिशन सभी की सक्रिय भागीदारी के साथ अग्र तथा पृष्ठ सम्पर्क सुनिश्चित करते हुए बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए देश में इस मिशन का संचालन कलस्टर एप्रोच से किया गया है[6]।

सिक्किम सहित 8 पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड राज्यों को छोड़कर इस मिशन का क्रियान्वयन सम्पूर्ण भारत में किया जा रहा है। इस मिशन को विस्तारित करते हुए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में इसे सौ प्रतिशत की सहायता, जिसमें 85 प्रतिशत का योगदान केन्द्र सरकार और शेष 15 प्रतिशत की सहायता राशि राज्य सरकारें उपलब्ध करवाती है। जिसमें हितग्राहियों को 70 प्रतिशत भौतिक रूप से और 30 प्रतिशत आर्थिक मदद का प्रावधान है।

मिशन के उद्देश्य: राष्ट्रीय बागवानी मिशन के प्रमुख उद्देश्य निम्न है–

1. प्रत्येक राज्य/क्षेत्र के तुलनात्मक लाभ और उसके भिन्न कृषि–जलवायु विशेषताओं के अनुरूप क्षेत्र आधारित भिन्न कार्यनीतियों के माध्यम से बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास करना, जिसमें अनुसंधान, प्रौद्योगिकी संवर्धन, विस्तार, कटाई–पृष्ठ प्रबंधन, प्रसंस्करण एवं विपणन शामिल है।
2. बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना, पोषण सुरक्षा में सुधार और कृषि परिवारों की आय में समर्थन प्रदान करना।
3. बागवानी विकास हेतु योजना एवं कार्यक्रमों के मध्य अभिसरण तथा समन्वय स्थापित करना।
4. पंरपरागत विवेक रहित और आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के मिश्रण के माध्यम से बागवानी विकास हेतु प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना एवं विकसित कर प्रसार करना।
5. कुशल तथा अकुशल व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजन अवसरो को उत्पन्न करना, विशेष रूप से बेरोजगार व्यक्तियों हेतु।

कार्यनीतिः 1. उत्पादन, कटाई–पृष्ठ प्रबंधन, प्रसंस्करण और उत्पादकों को उचित प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए विपणन को कवर करने वाली सिरे से सिरे की एक समग्र सोच को अपनाना।
2. उत्पादन कटाई–पृष्ठ प्रबंधन तथा प्रसंस्करण हेतु अनुसंधान एवं विकास प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।
3. उत्पादन में वृद्धि के लिए संचयन करना।
4. सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण तथा मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देना।

एन.एच.एम. की वित्तीय प्रगतिः मिशन की वित्तीय प्रगति में वर्ष 2005–06 से 2009–10 तक 4303.12 करोड़ रूपए की धनराशि प्रदान की गई है जिसमें से 4125.43 करोड़ रूपए व्यय हुए है और वर्ष 2010–11 में 1061.98 करोड़ रू. प्रदान किये गए है और 801.38 करोड़ रू. स्कीम के कार्यान्वयन हेतु निर्मुक्त हुए है।

एन.एच.एम. की भौतिक प्रगतिः राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत बागवानी क्षेत्र की भौतिक प्रगति को निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया है–

तालिका क्र.4
एन.एच.एम. के अंतर्गत भौतिक प्रगति

(क्षेत्र– लाख हैक्टेयर में)

क्र.सं.	मद	2005–06 से 2009–10	2010–11,जनवरी 11 तक
1	नर्सरियॉ(संख्या)	2192	55
2	विस्तारित क्षेत्र	16.51	2.10
3	जराग्रस्त पौधें का पुनरूद्धार	2.78	0.37
4	जैविक कृषि	1.37	0.05
5	समेकित कृषि प्रबंधन व पोषक तत्व	7.53	1.04
6	पैक हाउस (संख्या)	1091	546
7	शीत भण्डारण (संख्या)	367	43
8	मण्डी (संख्या)	172	9
9	मोबाईल/प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट	264	69

स्रोतः वार्षिक रिपोर्ट:2010–11 कृषि मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि देश में एन.एच.एम. के तहत बागवानी विकास में काफी रूप से भौतिक वृद्धि दर्ज की गई जिसमें बागवानी क्षेत्र के विस्तार में सत्र 2010–11 में 2.10 लाख हेक्टेयर भूमि को कवर किया गया है। इसी प्रकार जैविक कृषि के अंतर्गत इसी वर्ष 0.05 लाख हैक्ट. पर जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया।

निष्कर्ष: देश के कृषि विकास में बागवानी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि यह कृषि क्षेत्र में अवसरों के विकल्पों का सृजन और कृषि में विविधीकरण को बढ़ावा कर कृषि क्षेत्र के विकास को परिपूर्ण करने में उल्लेखनीय योगदान का निर्वाह करता है, क्योंकि बागवानी फसलें उगाना आजीविका सुरक्षा सुधारने, रोजगार सृजन बढ़ाने, खाद्य और पोषाहारीय सुरक्षा प्राप्त करने, मूल्यवर्धन के जरिए आय बढ़ाने का एक विकल्प है। लेकिन आज कृषि के समक्ष अनेक चुनौतियॉ विद्यमान है जिसके कारण से कृषि अपनी दरिद्रता से ग्रस्त है। विश्व में भारत की कृषि की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हालांकि बागवानी क्षेत्र कृषि विकास कुंजी के रूप में उभरा है किन्तु बागवानी के विकास के लिए आज फिर से हरित क्रांति की आवश्यकता है इसके साथ ही बागवानी विकास के लिए सरकार को ग्राम पंचायत स्तर कार्यशाला एवं उपज की बिक्री की ग्यारण्टी, भण्डारण, विपणन के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने की पहल और कृत्रिम वर्षा जैसे उपायों के साथ शोध कार्यो का विस्तार भी करना चाहिए। अतः इस नीतिगत पहल से देश में बागवानी विकास की संभावनाओं के साथ विकास की अनुकूल दशाऍ भी अधिक मौजूद है, जिससे कम लागत में अधिक प्रतिफल प्राप्त किया जा सकता हैं। बागवानी विकास का प्रमुख कार्यक्रम ''राष्ट्रीय बागवानी मिशन'', इस क्षेत्र के विकास में दीपक की तरह कार्य कर रहा है।

संदर्भ सूचीः

1. प्रतियोगिता दर्पण, ''भारतीय अर्थव्यवस्था', (2012), उपकार प्रकाशन, आगरा ।
2. रिपोर्ट, (नवम्बर 2011), वर्किंग ग्रुपः बागवानी और पौधीय फसलें, (योजना आयोग, बारहवीं पंचवर्षीय योजना), राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड़, गुड़गांव।
3. वार्षिक रिपोर्ट, (2010–11), कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
4. सांख्यकीय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
5. बागवानी डाटाबेस, 2010, (एन.एच.बी.)
6. www.nhm.com

****